संख्याः 463 /VIII/11-09(कराबीयो)/2011

प्रेशक.

किशन नाथ, अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, देहरादून।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून, दिनाँक (8 अप्रैल, 2011

विषयः—वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय—व्ययक की वचनबद्ध/आवश्यक मदों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:— 209/XXVII(1)/2011 दिनांक 31 मार्च, 2011 के क्रम में एवं वित्तीय वर्ष 2011—12 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना हेतु ब्यौरेवार अनुमान में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अनुदान संख्या—16 में लेखाशीर्षक—2210 के अन्तर्गत वचनबद्ध/आवश्यक मदों की संलग्न विवरणानुसार आयोजनेत्तर पक्ष में रू० 5,90,37000 (रू० पांच करोड़ नब्बे लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आंबटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंधन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3— उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011—12 के अनुदान संख्या 16 के मुख्य लेखाशीर्षक 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

- प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण–वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो। धनराशि का उपयोग दि० 31 मार्च, 2012 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी०एम0-13 शासन में उपलब्ध कराया जाएगा।
- अवचनबद्घ मानक मदों में धनराशि अवमुक्त किये जाने का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाये, ताकि वित्त विभाग की सहमति से आवश्यक धनराशि अवमुक्त की जा सके।
- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या—209/XXVII(1)/2011, दिनांक 31 मार्च, 2011 में दिए गए निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,

(किशन नाथ) अपर सचिव

संख्याः 463 (1)/VIII/11-09(कराबीयो)/2011, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तराखण्ड। _2_

एनआईसी, सचिवालय।

वित्त अनुभाग-5।

गार्ड फाइल।

आज्ञा से.

शासनादेश संख्या:-1-65/VIII/11-09(कराबीयो)/2011,दिनांक/8 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

अनुदान संख्याः 16

धनराशि हजार रूपये में

(I) लेखाशीर्षक

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाष्वात्य चिकित्सा पद्धति

102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना

01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (88: के०सं०)

0103 अधिष्ठान (निदेशालय)

क्र0सं0		मानक मद संख्या का नाम	आयोजनेत्तर
1	01	वेतन	2200
2	02	मजदूरी	50
3	03	महंगाई भत्ता	1320
4	06	अन्य भत्ते	242
5	09	विद्युत देय	10
6	10	जलकर / जलप्रभार	5
7	17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	300
8	27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
9	39	औषधि तथा रसायन	8000
योग:			12177

(रुपये एक करोड़ इक्कीस लाख सत्तहर हजार मात्र)

(II) लेखाशीर्षक

2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाष्वात्य चिकित्सा पद्धति

102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना

01 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें (88: के०सं०)

0104 क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान श्रम विमाग द्वारा

क्र0सं0		मानक मद संख्या का नाम	आयोजनेत्तर
_ 1	01	वेतन	15000
2	02	मजदूरी	100
3	03	महंगाई भत्ता	9000
4	06	अन्य भत्ते	1650
5	09	विद्युत देय	50
6	10	जलकर / जलप्रभार	10
7	17	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	850
8	27	चिकित्सा व्ययं प्रतिपूर्ति	200
9	39	औषधि तथा रसायन	20000
योग:			46860

(रुपये चार करोड़ अडसठ लाख साठ हजार मात्र)

महायोग:- रू० 5,90,37000 (रू० पांच करोड़ नब्बे लाख सैंतीस हजार मात्र)

(किशन नाथ) अपर सचिव